SHRI BHUBANESWAR KALITA: What is the allocation of funds for the year 1992-93 for the N.E.C.? What is the State-wise allocation for different schemes?

SHRI S. B CHAVAN: There is a public document which is being published. If you refer to the Budget, Budget papers, you can get this information.

SHRI HIPHEI; Madam, the Home Minister is stating of those schemes which are of national character. Now, for a State like Mizoram we can never have schemes (hat have a regional character because Mizoram is a border State...

THE DEPUTY CHAIRMAN: If you are brief, then I can allow. I think he has already answered your question. *(Interruption)* ... It is being answered already Question No. 205 Dr. Bapu Kaldate.

लघु उद्योग एककों को कोयले की सप्लाई के लिए वैगनों का उपलब्ध न होना

*205. डा० बापू कालदाते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी भारत में लघु उद्योग एककों को कोयले की सप्लाई के लिए अपेक्षित संख्या में वैगन उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा लघु उद्योग एककों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) चूंकि कुल मिलाकर कोयले की मांग, उस की उपलब्धता और रेल रिवहन क्षमता से कहीं अधिक है तथा ताप बिजली घर, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, रेलवे, आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कोयले की सप्लाई को उच्चतर प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों, जिनमें उत्तर भारत के लघु उद्योग एकक भी शामिल हैं, को उनके कार्यक्रम के अनुसार कोयले की सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही है ।

(ग) कोयला मंत्रालय ने सभी कोयला कपनियों को अनुदेश दिये हैं कि लघु उद्योग एककों सहित गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं को कोयले की कम से कम 50 प्रतिशत संबद्ध मात्रा, रेल अथवा सड़क मार्ग द्वारा सप्लाई की जाए ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Threat of armed struggle by Ladakhi Budhists

*206. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Ladakhi Buddhists have been agitating for an autonomous State for Ladakh and have threatened to resort to armed struggle to achieve the objective;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(d) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): (a) to (c) The Ladakh Buddhist Association (LBA) was demanding grant of Union Territory Status which was dropped by them after an agreement on 29th October, 1989, reached in the presence of the then Union Home Minister. As a part of the Agreement, the Government of Jammu and Kashmir, among other items, also promised to examine and consider the demand for an autonomous District Hill Council and to formulate an integrated tribal sub-plan within a time-frame.

Recently, official level talks have been held with the representatives from Leh and Kargil Districts of Ladakh Region in May and June, 1992. The Government considers that communal amity, preserving identity of Ladakh, and setting up of suitable institutional arrangements to meet the aspirations of the people of this remote border region are all important requisite for a lasting solution.

राष्ट्रीय राजमार्गों की दशा में सुधार किया जाना

***207. श्री विनोद शर्मा :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री 26 फरवरी, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 384 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों की दशा में सुधार करने के लिए लगभग 2,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस पूंजीगत निवेश से देश का ईंधन की खपत में प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपए की बचत करने में मदद मिलेगी, और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गठित सड़क संबंधी कार्य-दल ने राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए 8300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के प्रस्तावों की सिफारिश की थी जिससे ईंधन सहित वाहन प्रचालन लागतों में 2300 करोड़ रुपये का संभावित बचत होगी । तथापि, योजना आयोग ने 8वीं योजना के लिए केंद्रीय सेक्टर/केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के लिए जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल है, केवल 2600 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया है । ईंधन उपयोग सहित वाहन प्रचालन लागतों में वास्तविक बचत, योजनावधि, के दौरान आवंटित राशि और किए जाने वाले सुधार कार्यों की प्रकृति पर निर्भर करेगी ।

दिल्ली में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि

***208. श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके परिणाम-स्वरूप गत तीन महिनों के दौरान राज-धानी में बम विस्फोट, हत्या और लूट पाट की कितनी घटनाएँ हुई हैं और सरकार ने उन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस0 बी0 चव्हाण) : (क) और (ख) गत तीन महीनों, अर्थात् 1-4-1992 से 30-6-1992 तक की अवधि के दौरान आतंकवादियों द्वारा लूट-पाट करने की कोई घटना नहीं हुई है । बम विस्फोट की पांच घटनाएँ हुई हैं जिसके परिणामस्वरुप एक व्यक्ति मारा गया । गोली चलानें की दो घटनायें हुई जिसके फलस्वरूप , दो आतंकवादियों सहित, चार व्यक्ति मारे गए ।

राजधानी में आतंकवादियों गतिविधियों को रोकने के लिए किए गए उपायों में प्रत्येक जिले में एक आतंकवाद-विरोधी सैल गठित करना, संवेदनशील/सामारिक महत्व के स्थानों पर पुलिस टुकड़ियां तैनात करना, चलती-फिरती गश्त को तेज करना, लोगों को और सतर्क करने के लिए उनमें शिक्षाप्रद साहित्य का वितरण करना, भेदियों को तैनात करना, सार्वजनिक स्थानों पर ज्ञात आतंकवादियों को फोटों लगना, सामरिक महत्व के स्थानों पर पी.सी.आर. वाहन तैनात करना, तथा पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बैठकें करना शामिल हैं ।